>

Title : Need to provide special financial package to the State of Rajasthan to make up the shortfall in the number of teachers and remove shortcomings in the educational system.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मैं सदन का ध्यान देश के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके कारण अध्यापन कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। विशेषकर, राजस्थान राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में प्रत्येक जिले में अध्यापकों की कमी है। शिक्षण व्यवस्था ठीक न होने से आए दिन विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गुस्साए छात्र एवं अभिभावक विद्यालयों में ताला लगा देते हैं। विज्ञान विषय की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं होती है। भारत के संविधान में 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ नःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का यह संकल्प तभी पूरा होगा जब प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप अध्यापक होंगे तथा अध्यापन कार्य समय से होगा। शिक्षा में राजस्थान राज्य अन्य प्रदेशों की तुलना में पिछड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने वाले बालकों के लिए आधुनिक तकनीकी आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रभावी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जब केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 65 प्रतिशत व राज्य सरकार को 35 प्रतिशत के अनुपात में राशि अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए दी जा रही है, फिर भी राज्य में बालकों की उच्च शिक्षा के प्रति उठाए गए कदम नाकाफी हैं।

अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान राज्य में अध्यापकों की कमी को देखते हुए विशेष पैकेज दिया जाये तथा शैक्षणिक व्यवस्था में हो रही कमी को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जाये।